(ii) STEPS TO AVERT THE REPORTED STRIKE BY JUNIOR DOCTORS FEDERATION, DELHI.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule 377, I want to mention the following matter of urgent public importance.

The junior doctors' federation, Delhi has reportedly threatened that if its demands are not met by July, 4, 1980, an indefinite strike would start in all the major hospitals from the next day. They had observed a token strike earlier, for a day on 16th June, 1980. In view of the fact that the resident doctors form the backbone and the infrastructure of any hospital service, the resulting inconvenience to the people can be readily realised. It is, therefore, of utmost importance that the Government should take every step to avert the strike. That the resident doctors are not motivated with any spirit of confrontation is amply clear from the fact that they are agreeable to the appointment of a high-powered committee, which should include the representative of the federation, to look into the various aspects of their demands. This is a gesture that should get a positive response from a Government that is interested in both the solution of the problems of resident doctors as also in averting any inconvenience or hardship that may be caused to the people, through any such strike.

It is rather unfortunate that, as I understand, the office of the Minister for Public Health refused to accept the memorandum which the junior doctors' federation wanted to submit on 20th June, 1980 with respect to their proposed strike from 5th July. A positive, constructive and sympathetic attitude is necessary. I urge upon the Government to have a purposeful dialogue with the resident doctors. I request the Government to make an early statement in the House and reassure the House and the people of Delhi that every effort will be made to avert the proposed strike.

(iii) REPORTED LOSS TO FARMERS DUE TO WATER LOGGING BY THE GHAGGAR FLOOD PROJECT AND RAJASTHAN CANAL PROJECT.

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान प्रान्त के उस पीड़ित क्षेत्र की दुर्दशा की तरफ खींचना चाहता हूं जहां लगभग 15 गांवों के रिहायशी मकान और खेती की जमीनें घग्घर बाढ़ परियोजना और राजस्थान नहर के आर० डी० 165 से छोड़े गये पानी से बने सेमें में घिर गई हैं, जिससे किसानों का करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। इन 15 गांवों के किसान भूमिहीन और बेघर हो गये हैं । एक तरफ सरकार बाढ़ नियंत्रित कर के कहीं लोगों को सुरक्षित कर रही है तो दूसरी तरफ उसी बाढ़ के पानी से इन लोगों की तबाही कर रही है तथा पीड़ित लोगों को कोई राहत भी नहीं पहुंचाई जा रही है । पिछले तीन वर्षों से बड़ोपल, मानकथेड़ी, किशनपुरा आदि गांवों के लोगों ने बार-बार तत्कालीन, "जनता सरकार" से आग्रह किया, हड़तालें की मगर इन दुखियों की तरफ जनता सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कहीं सुनवाई न होने पर गत विधान सभा चुनाव में एक गांव मानकथेड़ी ने तो मतदान का बहिष्कार भी कर दिया । प्रजातंत्र में ऐसा बहिष्कार प्रजातंत्र को ही एक चुनौती है । बेसहारा लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष 19–5–80 से 16–6–80 तक क्रमिक भूख हड़ताल भी की परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों के कोई ध्यान न दिये जाने पर, बेबस लाचार हो कर 17–6–80 से दो व्यक्तियों ने सूरतगढ़ में आमरण अनशन कर रखा है । ये दोनों ही व्यक्ति मरणासन्न हैं ।

अतः यदि सरकार ने समय पर इनकी मांगे मान कर राहत न पहुंचाई तो इनके प्राण पखेरू उड़ जायेंगे और सरकार पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जायेगा । इस बात को ले कर क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है । इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि इस गम्भीर समस्या पर अविलम्ब कार्यवाही करने के आदेश राजस्थान सरकार को दे कर, उन पीड़ित व्यक्तियों की मांगें मानी जायें तथा उस क्षेत्र की इस विकट समस्या, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, का कोई स्थायी समाधान निकालने की व्यवस्था की जाये ।

(iv) NEED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO APPLE GROWERS IN HIMACHAL PRADESH.

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule 377, I wish to bring the follow-